



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 298]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 20, 2008/श्रावण 29, 1930

No. 298]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 20, 2008/SRAVANA 29, 1930

बाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(बाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2008

सं. 67 (आर.ई.-2008)/2004—2009

फा. सं. 01/36/218/26/एएम 09/पी सी-5/
ईपीसीजी-1.—विदेश व्यापार नीति, 2004—2009 के ऐसांगक 2.4 के
तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार,
एसट्राय, प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-1 (आर.ई.-2008) में, निम्नलिखित
संशोधन करते हैं :

1. सार्वजनिक सूचना सं. 26 (आर.ई.-2008)/2004—2009
दिनांक 3 जून, 2008 द्वारा ऐसांगक 5.11.3 के आद जोड़े गए ऐसांगक
को संशोधित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :—

“बद किसी उत्पाद के नियंत्रण पर रोक/प्रतिबंध लगाय
जाता है, तो ऐसे नियंत्रण उत्पादों पर रोक/प्रतिबंध लगाने से
पूर्व पहले से जारी ही सी जी प्राधिकार पत्रों के संबंध में
नियंत्रण दायित्व की अवधि बिना किसी संयोजन शुल्क के
रोक/प्रतिबंध की अवधि के बराबर स्वतः ही बद जाएगी
और नियंत्रक को रोक/प्रतिबंध की अवधि को लिए औसत
नियंत्रण दायित्व को भी पूरा करने की आवश्यकता नहीं
होगी।”

2. इसे लोकाहित में जारी किया जाता है।

आर. एस. गुजराल; महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन अफर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 20th August, 2008

No. 67 (RE-2008)/2004—2009

F. No. 01/36/218/26/AM 09/Pol. V/EPCG-L.—In
exercise of powers conferred under paragraph 2.4 of the
Foreign Trade Policy, 2004—2009, the Director General of
Foreign Trade hereby makes the following amendments in
Handbook of Procedures, Vol. I (RE-2008) :

1. The following paragraph added after paragraph
5.11.3 vide Public Notice No. 26 (RE-2008)/2004—2009 dated
3rd June, 2008 stands amended to read as under :—

“Whenever a ban/restriction is imposed on export
of any product, export obligation period in respect
of EPCG authorizations already issued prior to
imposition of ban/restriction of such export
products, would stand automatically extended for
a period equivalent to the duration of ban/
restriction, without any composition fee and
exporter would not be required to fulfill average
E.O. as well, for the ban/restriction period.”

2. This issues in public interest.

R. S. GUJRAL, Director General of Foreign Trade
& ex-officio Addl. Secy.